

[2008] 10 एस.सी.आर 1161

कर्नाटक राज्य

बनाम

बंतरा सुधाकर उर्फ सुधा और अन्य

(2001 की आपराधिक अपील संख्या 288)

18 जुलाई, 2008

।डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम और अफताब आलम, जे.जे।

दंड संहिता, 1860, धारा 376

नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार-प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र। अभियोजक की आयु 16 वर्ष से कम दिखाने वाले न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध करने का दोषी पाया। बलात्कार किया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किया गया। अभियोजक की आयु 16 वर्ष से अधिक रखने वाला न्यायालय और यह कि सहमति थी, की शुद्धता-आयोजित की गई, गलत है। अभियुक्त व्यक्तियों ने यह दलील नहीं दी कि सहमति थी, उच्च न्यायालय ने पीड़ितों की आयु 16 वर्ष से अधिक लेने में और हेड मास्टर

के साक्ष्य कि पीड़ित की आयु 16 वर्ष से कम है, को नकारने में गलती की। उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष न केवल भ्रामक हैं, बल्कि अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय टिकाऊ नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति-ताई लॉर्स पेशे से पीड़ित-बहनों को ब्लाउज की डिलीवरी देने के बहाने जिन्हें उन्होंने सिलाई के लिए दिया था अपने निवास ले गया। अभियुक्त ने पीड़ितों के साथ बलात्कार किया और घटना का खुलासा करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जब पीड़ित घर नहीं लौटे, तो पीड़ितों के बड़े भाई पीडब्लू-17, रिश्तेदारों के घर गए और दोनों को पाया। वह उन्हें वापस ले आया और फिर दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल अदालत ने उन्हें बलात्कार का अपराध करने का दोषी पाया और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि पीड़ितों की उम्र 16 साल से अधिक की थी और सहमति थी। इसलिए वर्तमान अपील □□□ □□ ।

अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि प्रत्येक पीड़ित की आयु 16 वर्ष से अधिक थी, और यह कि सहमति के संबंध में कोई याचिका नहीं थी और इसलिए उच्च न्यायालय अपने आप सहमति का मामला नहीं बना सकता था।

उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक परिदृश्य स्पष्ट रूप से सहमति और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को दर्शाता है। आयु और सहमति के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए,

माना:- पीडब्लू **16**-शिक्षक ने प्रमाण पत्रों को संदर्भित किया, जिसमें संकेत दिया कि पीडब्लू **1** की जन्म तिथि **5.3.1974** थी और पीडब्लू **2** की जन्म तिथि **1.2.1974** थी। उच्च न्यायालय ने एक्स-रे रिपोर्ट के संदर्भ में महिला डॉक्टर पीडब्लू **24** के साक्ष्य का हवाला दिया, जो इंगित करता है कि पीडब्लू की आयु कितनी है। पीडब्लू **1** और **2** की उम्र **14** से **16** साल के बीच थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि दो साल के अंतर की संभावना है और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि पीड़ितों की उम्र **16** साल से अधिक थी। जहाँ तक उच्च न्यायालय के तर्कों का संबंध है, उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। □□□□□□□□□□ □□□ □□, उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि पीडब्लू **16** प्रधान शिक्षक के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज किया जाना था कि जन्म तिथि किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दर्ज नहीं की गई होगी ताकि यह दिखाया जा सके कि ये दो लड़कियां, पीड़ित, उस तारीख को पैदा हुई थीं जैसा कि उल्लेख किया गया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष न केवल भ्रामक हैं, बल्कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत हैं। उच्च न्यायालय ने एक और निष्कर्ष दर्ज किया कि दोनों प्रमाण पत्र पीड़ितों से संबंधित नहीं हो सकते हैं, हालांकि यह विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि इस तरह की कोई चुनौती नहीं

उठाई गई थी। इसके अतिरिक्त, केवल चिकित्सक की जांच से साक्ष्य का पता चला कि पीड़ित **14** और **16** साल के आयु वर्ग के हैं, इससे यह निष्कर्ष निकालना कि दो साल की उम्र ज्यादा मानी जानी आधार नहीं था। किसी भी घटना में, आरोपी व्यक्तियों ने यह रुख नहीं अपनाया कि कोई सहमति थी। (पैरा **7**) [**1166-सी, डी, ई, एफ, 1167-ए, बी**]

एच.पी. बनाम राज्य श्री कांत शेखर (2004) 8 एस.सी.सी. 153- पर भरोसा किया।

2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से स्थिर नहीं है और विचारण न्यायालय कोर्ट के फैसले को बहाल किया जाता है। (पैरा **8**) [**1168-ई, एफ**]

मामला कानून संदर्भ

(2004) 8 एस.सी.सी. 153 के पैरा **7** पर निर्भर किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की आपराधिक अपील संख्या 288

आपराधिक अपील सं.202, 1995 में बेंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 7.9.2000 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से संजय आर.हेगड़े, अमित के.चावला और ए.रोहन सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से डी.के. सिंह और राजेश महाले।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. के द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें उत्तरदाताओं को बरी करने का निर्देश दिया गया था, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

2. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 अपने-अपने माता-पिता के साथ मदेनाडु में रह रहे थे और वे पुदियेंदा पलंगप्पा के कॉफी एस्टेट में कुली के रूप में काम कर रहे थे, अपीलकर्ता नंबर 2 (अभियुक्त नंबर 2) पेशे से एक दर्जी है, जिसकी आटेकेरे में सिलाई की दुकान है। दिनांक 16-9-1989 को सुबह लगभग 9.00 बजे, पीडब्लू 1 और ए-2 की सिलाई की दुकान पर गए और उनसे उनके ब्लाउज सिलने का अनुरोध किया। उस वक्त उन्होंने नए कपड़ों के साथ अपने दो ब्लाउज भी नाप के लिए दे दिए। आरोप है कि ए-2 ने उनसे अगले दिन आकर ब्लाउज सिलने की स्थिति में डिलीवरी लेने को कहा। तदनुसार, दिनांक 17.9.1989 को वे दोनों कपड़ों की डिलीवरी लेने के लिए टेलरिंग की

दुकान पर गए, जब ए-2 ने उन्हें सूचित किया कि सिलाई पूरी नहीं हुई है, जिस पर दोनों ने उससे माप के लिए दिए गए ब्लाउज वापस करने के लिए कहा। इसके जवाब में, ए-2 ने उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा क्योंकि ब्लाउज उनके घर में रह गए थे। तदनुसार, वे दोनों ए-1 और ए-2 के साथ उस घर में गए जो पास में था। ए-1 एवं ए-2 गये घर के अंदर और जब वे लगभग 15 मिनट तक घर से बाहर नहीं आये, तो दोनों पीडब्लू. 1 और 2 जो बाहर इंतजार कर रहे थे, घर में दाखिल हुए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, ए-2 ने दरवाज़ा बंद कर दिया और पीडब्लू2 को पकड़ लिया और ए-1 ने भी पीडब्लू. 1 को पकड़ लिया। उन्हें अलग-अलग कमरों में ले जाया गया और ए-1 ने पीडब्लू. 1 के साथ बलात्कार किया और ए-2 ने PW2 के साथ बलात्कार किया, इसके बाद, उन्होंने दोनों को धमकी दी कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया गया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए, वे चुप रहे। दिनांक 18-9-1989 को वे चंद्रकला (पीडब्लू 14) के घर मदिकेरी गए। उस रात चंद्रकला के घर में रुकने के बाद, वे पीडब्लू 2 के चाचा के घर सुलिया गए। चूंकि पीडब्लू 1 और 2 अपने घरों में नहीं पाए गए, पीडब्लू 1 और 2 के माता-पिता ने शेषप्पा (पीडब्लू-17) को, जो पीडब्लू 2 का बड़ा भाई है, सुलिया में उसके मामा के घर भेजा। तदनुसार, वह सुलिया स्थित घर गए और उन दोनों को ढूंढा और उन्हें मदेनाडु वापस ले आए, इसके बाद, वे 21-9-

1989 को मदिकेरी ग्रामीण पुलिस स्टेशन गए और पीडब्लू 1 द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित शिकायत पूर्व-पीएल प्रस्तुत की, जिसे प्राप्त कर लिया गया। पीडब्लू 26 द्वारा शाम 6.45 बजे उस दिन, पीडब्लू 26 ने मदिकेरी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सीआर क्रमांक 233/89 में मामला दर्ज किया और पूर्व-पी.33 के अनुसार एफआईआर प्रस्तुत की। अगले दिन उन्होंने उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल, मदिकेरी भेजा। पीडब्लू. 1 और 2 ने वे कपड़े भी पेश किए जो उन्होंने घटना के समय पहने हुए थे जिन्हें जब्त कर लिया गया। पीडब्लू 26 घटनास्थल पर गया जो कि ए-2 का घर है जहां पीडब्लू 1 और 2 पर कथित बलात्कार किया गया था। उन्होंने पंचों की उपस्थिति में पीडब्लू 2 के घर में महाज़ार एक्स-पी 4 को खींचा और टूटी हुई चूड़ियाँ एमओ को जब्त कर लीं जो 8 और 9 है। उन्होंने एक्स-पी 3 के अनुसार ए-2 की दुकान में महाज़ार भी खींचा और पीडब्लू 1 और 2 द्वारा सिलाई के लिए दिए गए कपड़े जब्त कर लिए। दिनांक 23-9-1989 को ए-1 को गिरफ्तार कर लिया गया। पीडब्लू-26 ने ए-1 का बयान दर्ज किया जो उन्हें अपने घर ले गया जहां उसने एक्स-पी.33 के अनुसार एक महाज़ार बनाया। इसके बाद, आगे की जांच पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर पीडब्लू 24 द्वारा की गई। 13-11-1989 को ए-2 अग्रिम जमानत के आदेश के साथ उनके समक्ष उपस्थित हुआ। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया।

उसने अपने घर से वह कपड़े भी पेश किये जो उसने घटना के समय पहने हुए थे, जिन्हें Ex-P.29 के अनुसार जब्त कर लिया गया। ए-1 और ए-2 दोनों की चिकित्सा जांच की गई, डॉ. जी. मारुलासिद्दप्पा (पीडब्लू 25) ने पूर्व-पी.27 के अनुसार ए-1 का प्रमाण पत्र जारी किया और डॉ. सूर्यकुमार (पीडब्लू-3) ने पूर्व पी.6 के अनुसार ए-2 का प्रमाण पत्र जारी किया गया। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, क्योंकि इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस प्रतिबद्धता आदेश की प्राप्ति पर, सत्र न्यायालय, कोडागु जिले ने एक मामला (एससी संख्या 45/90) दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए। 376 आईपीसी, और दोनों अपीलकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष के मामले को प्रमाणित करने के लिए, इसने 27 गवाहों की जांच की और एक्सएस-पी 1 से पी.34 और एमओ 1 से 24 को भी चिह्नित किया।

3. उत्तरदाताओं का मामला यह था कि कुछ संपत्ति विवाद के मद्देनजर, पीडब्लू 1 और 2 ने उनके खिलाफ झूठा मामला दायर किया और वे निर्दोष हैं।

4. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, विशेष रूप से स्कूल के शिक्षक (पीडब्ल्यू 16) द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों के संदर्भ में पाया कि प्रत्येक मामले में पीड़ितों की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इसलिए विचारण न्यायालय ने माना कि सहमति का प्रश्न अप्रासंगिक और सारहीन है। अपील में, उच्च न्यायालय ने माना कि उम्र 16 वर्ष से अधिक थी और सहमति थी और तदनुसार बरी करने का निर्देश दिया।

5. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गंभीर त्रुटि की है कि प्रत्येक पीड़ित की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। इसके अलावा सहमति के संबंध में कोई दलील नहीं थी और इसलिए उच्च न्यायालय अपने आप सहमति का मामला नहीं बना सकता था।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा कि तथ्यात्मक परिदृश्य स्पष्ट रूप से सहमति दर्शाता है और उम्र और सहमति के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षक-पीडब्लू 16 ने उन प्रमाणपत्रों का उल्लेख किया है जो दर्शाते हैं कि पीडब्लू 1 की जन्म तिथि 5.3.1974 थी और पीडब्लू 2 की जन्म तिथि 1.2.1974 थी। प्रदर्श पी.16 एवं पी.17 प्रमाण पत्र हैं। उच्च न्यायालय ने एक्स-रे रिपोर्ट के संदर्भ में महिला डॉक्टर पीडब्लू 24 के

साक्ष्य का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि पीडब्लू 1 और 2 की उम्र 14 से 16 साल के बीच थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि दो साल के अंतर की संभावना है और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि पीड़ितों की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। हाई कोर्ट ने माना कि यौन संबंध हुआ था और झूठा फंसाने की दलील खारिज कर दी। इसके बाद यह सहमति के सवाल की जांच करने लगा। जहां तक उच्च न्यायालय के तर्कों का सवाल है, वे बेतुकेपन की सीमा पर हैं। सभी प्रकार के अनुमान और अटकलें लगाई जा चुकी हैं। अजीब बात है, यह देखा गया कि पीडब्ल्यू हेड मास्टर के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना था कि जन्मतिथि किसी भी मेडिकल प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी सबूत के आधार पर दर्ज नहीं की गई होगी ताकि यह दिखाया जा सके कि इन दोनों लड़कियों का जन्म उल्लिखित तिथि पर हुआ था। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष न केवल भ्रामक हैं बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत हैं। उच्च न्यायालय ने एक और निष्कर्ष दर्ज किया कि दोनों प्रमाणपत्र पीड़ितों से संबंधित नहीं हो सकते हैं, हालांकि यह विशेष रूप से दर्ज किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं था। इसके अतिरिक्त, आरोपी द्वारा उठाई गई चुनौती केवल इसलिए कि डॉक्टर के साक्ष्य से पता चला कि पीड़ित 14 और 16 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, यह निष्कर्ष निकालना कि दो वर्ष की आयु को ऊपरी आयु सीमा में जोड़ा जाना है, बिना किसी आधार के है।

ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं था। किसी भी घटना में, आरोपी व्यक्तियों ने यह रुख नहीं अपनाया कि कोई सहमति थी। इसके विपरीत, उन्होंने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एचपी राज्य बनाम श्री कांत शेखरी [2004 (8) एससीसी 153] में इसे इस प्रकार देखा गया कि:

"जिन कारकों को उच्च न्यायालय ने महत्व दिया है वे हैं (i) पीड़िता की उम्र, जो उच्च न्यायालय के अनुसार 16 वर्ष से अधिक थी। (ii) अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं रखा गया है कि पीड़िता कृत्य के लिए सहमति नहीं दी थी और (iii) पीड़िता और उसकी मां द्वारा कथित बलात्कार का जो समय बताया गया था, वह चिकित्सा साक्ष्य द्वारा असंभव था। इस तथ्य का विशेष संदर्भ दिया गया था कि एक बच्चे का जन्म 10.4.1979 को हुआ था और यदि कथित बलात्कार पीड़िता और उसकी मां द्वारा बताई गई अवधि के दौरान किया गया है, जो पूरी तरह से अलग-अलग अवधि रही होगी। अभियोजन मामले में भेद्यता जोड़ने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को भी उजागर किया गया था। हम सबसे पहले उम्र के सवाल से निपटेंगे। रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पता चला कि पीड़िता की उम्र 15 से 16 वर्ष के

बीच है। यह स्थापित करने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड पेश किए गए कि उसकी जन्मतिथि 10.4.1979 थी। प्रासंगिक दस्तावेज़ उदाहरण पीडब्ल्यू 6/ए से पीडब्ल्यू 6/सी हैं। उच्च न्यायालय का विचार था कि ये दस्तावेज़ पीड़िता की उम्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे क्योंकि एक अन्य दस्तावेज़ उदाहरण पीडब्ल्यू 7/ए था जो उच्च न्यायालय के अनुसार पीड़िता से संबंधित नहीं था। केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज़, उच्च न्यायालय के अनुसार पीड़ित से संबंधित नहीं था, जो उदाहरण पीडब्ल्यू 6/ए से उदाहरण पीडब्ल्यू 6/सी के साक्ष्य मूल्य को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये पीड़िता के स्कूल में दाखिले और उसकी पढाई की अवधि से जुड़े रिकॉर्ड थे। ये दस्तावेज़ निर्विवाद रूप से साबित करते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 10.4.1979 थी। इसलिए, घटना की तारीख पर और यहां तक कि जब 20.11.1993 को एफआईआर दर्ज की गई थी तब भी वह लगभग 14 वर्ष की थी। इसलिए, सहमति का सवाल वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। अन्यथा ऐसा भी प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर गलती कर गया है कि पीड़िता ने यह नहीं दिखाया है कि यह कार्य उसकी सहमति से नहीं किया गया था। यह दिखाना पीड़िता का काम नहीं था कि कोई सहमति नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से भी निष्कर्ष शुरू से ही गलत है, यानी उस चरण से जब एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके साक्ष्य में एक स्पष्ट बयान था कि पीड़िता के विरोध के बावजूद बलात्कार जबरन किया गया था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा यह दिखाने के लिए पीड़ित पर बोझ डालना गलत था कोई सहमति नहीं। सहमति का प्रश्न वास्तव में अभियुक्त द्वारा बचाव का मामला है और यह दिखाने के लिए सामग्री रखना उसका काम था कि सहमति थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिरह के दौरान और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (संक्षेप में 'कोड') के तहत दर्ज किए गए बयान में सहमति की दलील नहीं दी गई थी। वास्तव में संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए बयान में याचिका को पूरी तरह से नकारना और झूठा निहितार्थ था।"

8. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है और खारिज कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल किया

गया है। उत्तरदाताओं को शेष सजा भुगतने के लिए, यदि कोई हो, हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

9. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ट्विंकल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।